requiring industrial licence have been approved in the State of Madhya Pradesh.

(c) and (d) Besides, delicensing of food processing sector except for distillation and brewing of alcoholic beverages, sugar and items reserved for small scale sector, Government have provided various fiscal incentives like removal/reduction of excise duties on a large number of food products, packaging materials, machineries and reduction of custom duties on capital goods, etc., for development of food processing industries in the country including Madhya Pradesh. In addition, Government have also formulated and is implementing various developmental Plan schemes for the development of food processing industries, assistance under which are made available to viable projects including that from Madhya Pradesh.

रसोई गैस की मांग और आपूर्ति

1635. श्री अनन्तराम जायसवाल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति का मास-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में रसोई गैस की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच काफी अन्तर है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में अगले छ: माह में रसोई गैस की भयंकर कमी होने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा भविष्य में रसोई गैस की सामान्य आपूर्ति जारी रखने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (घ) देश में एल पी जी की संभावित मांग स्वदेशी उपलब्धता से काफी अधिक है। तथापि, योजनायें, विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर नये संयंत्रों को स्थापित करके तथा आयात के माध्यम से आपूर्ति बढ़ाकर एल पी जी की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता हेतु योजनाएं तैयार की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कंपनियों के माध्यम से जो कुछ एल पी जी उपलब्ध है उसके अतिरिक्त देश के अंतर्गत एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु सरकार ने निजी एजेन्सियों द्वारा एल पी जी के आयात एवं बिक्री के लिए भी अनुमति दे दी है। देश के अंतर्गत एल पी जी के विद्यमान उपभोक्ताओं की मांग को, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास कर्ज है, कमोवेश पूरी तरह पूरा किया जाता है। मोसमीपन पहलू तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा हाथ में लिए गए बाजार विस्तार के कारण एल पी जी की मांग में माह दर माह विविधता होती है। निकट भविष्य में देश के अंतर्गत एल पी जी की कमी के संबंध में कोई आशंका नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान एल पी जी की खपत के संबंध में ब्यौरे निम्नवत दिए हैं:

वर्ष	एल पी जी खपत (हजार मीट्रिक टन में)
1992-93	2866
1993-94	3113
1994-95	3466 (अनंतिम)

Relief package to exporters of processed food in Gujarat

1636. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state: (a) whether Government propose to provide any relief package to the exporters processed foods in the State of Gujarat;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of proposals received and cleared by Government in 1994-95 for the setting up of 100 percent EOUs in Gujarat, district-wise;

(d) the proposed total investment thereof; and

(e) the steps taken by Government to ensure that the exporters follow the R.B.I. guidelines?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (e): The Ministry of Food Processing Industries does not propose to provide any relief package to the exporters of processed foods during 1994-95. 7 proposals of processed foods under 100 per cent Export Oriented Units have been approved for the State of Gujarat, district-wise break-up of which is annexed as Statement. (See below) R.B.I. itself is the Rgulating Authority under the Foreign Exchange Regulation Act.